

अतीक, अली समेत 13 पर रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का आरोप

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड किया है। शहर की जाफरी कॉलोनी निवासी साबिर की शिकायत पर के बाद अब अतीक, उसके बेटे अली पुलिस ने एक करोड़ की रंगदारी माझदूर, महापूर्व, माझदूर के खिलाफ एक और सहित 13 के खिलाफ एक और

किया है। शहर की जाफरी कॉलोनी पुलिस ने एक करोड़ की रंगदारी माझदूर, महापूर्व, माझदूर के खिलाफ एक और साबिर की है साबिर ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल 2019 को वह अपने चकिया स्थित आवास पर था। उसी बुक अतीकअहमद के कहने पर उसका बोटा अली अपने अन्य साथियों के साथ असलहा लेकर पहुंचा। उनके पास पिस्टल और राइफल थी। ये सभी घर के बाहर खड़े होकर उसको बुलाने लोगों साबिर के मूताबेक असलम माझदूर ने जेल में बढ़ अतीक अहमद को कॉल किया

एफआईआर दर्ज की गई है। जेल से साजिश रचने के आरोप में और साबिर से कहा कि लो अतीक भाई से बात कर लो।

सिविल लाइंस पर शामियाना रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग, जान बचाकर भागे ग्राहक-दुकानदार; इलाके में दहशत

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। सिविल लाइंस में सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई। आग लगता देख दुकानदार और ग्राहक आनन फानन बाहर किए। रोड पर भी अफरातफरी मच गई। कर्मचारियों ने पानी डालकर लपटों को पहली तरफ दुकानों तक पहुंचने से रोका। जानकारी पर पुलिस और फायर बिगड़ की टीम पहुंच गई। आग से रेस्टोरेंट में रखा थामान जल गया है। गमीनत ही कई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल दमकलकर्त्ता आग को पूरी तरह से बुझाने में जुटे हुए हैं।



यूपी में दो चरणों में होंगे निकाय चुनाव, नतीजे 13 मई को, प्रयागराज, कौशांबी प्रतापगढ़ में 4 मई को होगी वोटिंग

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सूखे में दो चरणों में 17 महापार और 1420 पार्षद के चुनाव होंगे। चार मई को पहले और

डाला था। राज्य निर्वाचन आयुक मोज बुमार ने लखनऊ में तारीखों का ऐलान करते हुए कहा प्रदेश के 17 महापार और 1420 पार्षद के चुनाव होंगे। चार मई को पहले और



11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को नतीजे अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जाहां पर अतीरिक पुलिस लागाने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों का बैलट पेपर से गोट डाले जाएं। इसके अलावा 544 नगर पालिका अध्यक्ष तथा 7178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। पहले 3.35 करोड़ सदाताओं ने वोट

अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जाहां पर अतीरिक पुलिस लागाने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों का बैलट पेपर से गोट डाले जाएं। इसके अलावा 544 नगर पालिका अध्यक्ष तथा 7178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा। पहले 3.35 करोड़ सदाताओं ने वोट

श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति ने दिया आय व्यय का लेखा-जोखा

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। सगरा सुन्दरपुर बाजार में हनुमान जन्मोत्सव में हुए आय-व्यय का लेखा-जोखा को



बौद्ध प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सीमित में 66 हजार रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ था जो आयोजन में लगे साउड, डीजे

क्या अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी की टिकट पर लड़ेगी मेयर का चुनाव

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। बुधन जन समाज पार्टी

की सुप्रीमो ने सोमवार को ऐलान किया कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं चुनाव नहीं दिया जाएगा। बीएसपी को बैठक में शामिल हुई शाइस्ता परवीन लेकर चर्चा की वह बीएसपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उमेश पाल हत्या में साइज़कर्ता के रूप में शाइस्ता परवीन नाम आने वें बाद बीएसपी की ओर से असफल चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा।

मायावती ने दिया जवाब

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। बुधन जन समाज पार्टी

की सुप्रीमो ने सोमवार को ऐलान किया कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं दिया जाएगा। गोरतलब है की बीएसपी में शामिल हुई शाइस्ता परवीन लेकर चर्चा की वह बीएसपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उमेश पाल हत्या में साइज़कर्ता के रूप में शाइस्ता परवीन नाम आने वें बाद बीएसपी की ओर से असफल चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा।

29 दारोगा इधर से उधर किए गए

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। पुलिसज़ालिन से एक दर्जन से अधिक नए दरोगाओं को नई तैनाती मिल गई है। डीसीपी नगर दीपक भक्त ने 29 दरोगाओं की तैनाती की है। दरोगा पन कुमार सिंह को चौकी प्रभारी सगम, दारागाज, अनिल पांडेय को चौकी प्रभारी सगम, जारिटान, कमलेश कुमार को धूमनांज, कमलेश यादव को चौकी प्रभारी अक्षयत, लखन सिंह को नई चौकी झूसी, गिरीश चंद यादव को चौकी प्रभारी आदर्श नगर करेली, अरविंद को नाका चौकी और अमित को सज्जीमंडी चौकी प्रभारी बनाया है। इसके अलावा दूसरे जोन से नगर में ट्रांसफर दरोगा संजय यादव को राजपुर, चिकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुलतानपुर, अंबेकरनगर, बाराबर्गं, अमरेश, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झासी, लालन, ललतपुर में चुनाव होंगे। दूसरे चरण 11 मई को मरठ, हापुड, गोतम्बुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरायू, शाहजहापुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, नगर, कानपुर देहात, फरीखाबाद, इटावा, कन्नौज औरया, हमीरपुर, चिकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुलतानपुर, अंबेकरनगर, बाराबर्गं, अमरेश, बस्ती, संतकबीरनगर, अजमगढ़, मज, बिलिया, सोनभद्र, भद्रोही व बीरजापुर में वोटिंग होगा।

Transfer

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। इस अवसर पर एडीएम सिटी शी मदन कुमार, नगर मजिस्ट्रेट शी सत्यप्रिय सिंह सहित सभी सम्बंधित अधिकारियों उपस्थित रहे।

प्रयागराज। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कड़े निर्देश दिए, सभी मजिस्ट्रेट निरीक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैरिंग किया जायगा।

लिया। जनपद कवचहरी में लाइट, बिजली, सीसीटीवी के निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव को ल

सम्पादकीय

चुनावी चंदे पर नियंत्रण जस्ता

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत में हर विधायक अपने करिंगर की शुरूआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम करने के लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल समय की मांग है। भारत के 2009 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा दो अरब डॉलर खर्च किए गए। यह आंकड़ा 2014 में पांच अरब और 2019 तक 8.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत का पिछला आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। यह अमेरिकी आंकड़े से भी आगे निकल गया, वहाँ 2015 में हुए चुनाव में 6.5 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार, भारत में इस खर्च का 10-12% फीसद मतदाताओं को सीधे नकद भुगतान के रूप में है। हमारे यहाँ चुनाव खर्च को लेकर राज्य वित्तीय पोषण का मामला पहले से विचारणीय रहा है। इस मुद्दे पर अब नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, 2021-22 में देश में राष्ट्रीय दलों की आय का 60% फीसद अज्ञात स्रोतों से आया और यह राशि 2,172 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा 17,249 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से जुटाए गए। इसमें कहीं दो राय नहीं कि चुनिंदा सुधारों के बावजूद दशकों से देश में चुनावी खर्च में पारदर्शिता की कमी रही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951), धारा 29(सी) के मुताबिक, राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्षों को 20 हजार रुपये से अधिक के किसी भी योगदान के दस्तावेज चुनाव आयोग से साझा करना होता है। 1968 में इंदिरा गांधी की पहल पर राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अलबत्ता 1985 में इसे फिर से वैध ठहरा दिया गया। 1979 तक राजनीतिक दलों को आय और संपत्ति करों से भी छूट हासिल थी। हालांकि वे वार्षिक रिटर्न दाखिल करते थे और दस हजार रुपये से अधिक के दान और उसके दाताओं की पहचान का खुलासा करते थे। कहना नहीं होगा कि इस मामले में बाद में संशोधनों ने निगमों और राजनीतिक दलों की गोपनीयता को सामान्य नागरिकों के सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी

ऋतुएं नहीं धरती का सिस्टम ही है

क्सलें नहीं उंगेंगी। पेड़ों की असमयीत हो जाएगी। हवा में ऑक्सीजन नागरिकों की सबकुछ तहस नहस हो जाना है। एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जिनका मिजाज मौसम की तरह बदलता है यानी कि मौसम का कार्बोथाई मिजाज नहीं होता है। वो

डॉलर का घटता वैश्विक दबदबा और रुपये का बढ़ता रुतबा

दूसरे विकसित देशों के साथ अपनी रिश्ते मजबूत कर रहे हैं तथा उनमें से अनेकों की विदेशी मुद्राओं के संग्रहण को प्राथमिकता दे रहे हैं वैस्तव में यह चर्चा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का ही हिस्सा है। रूस-यूक्रेन युद्ध में वैश्विक स्तर पर अमेरिकी रुख का रूस और चीन, दोनों मिलकर मजबूती से जगाव देना चाहते हैं इसलिए सबसे पहले चीन ने अमेरिकी डॉलर के अपने भारी भरकम संग्रहण को अपनी मुद्रा

युआन में परिवर्तित किया। फिर रूस द्वारा वैश्विक स्तर पर इस बात को प्रमुखता से उठाया जाने लगा कि आने वाले समय में चीन की मुद्रा युआन को डॉलर की जगह लेनी चाहिए। हालांकि वैश्विक स्तर पर कुल विदेशी मुद्रा भंडार में चीन की मुद्रा का हिस्सा मात्र पांच फीसदी के आसपास ही है। आगामी अगस्त में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक में डॉलर के विरुद्ध अन्य मुद्रा का विकल्प अवश्य चर्चा में रहेगा।

लेकिन ब्रिक्स बैठक में भारत कभी भी युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक कारण हैं। चीन व रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के पीछे मुख्य निशाना भारत है। इसलिए ब्रिक्स के अंतर्गत चीन की मुद्रा को डॉलर के विकल्प के रूप में शायद ही देखा जाए। अब अगर भारत के विदेशी मुद्रा संग्रहण की बात की जाए, जो इन दिनों 530 अरब डॉलर के

आसापास है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का ही है। भारत की आर्थिक नीतियों का द्युकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा रहता है। हालांकि अमेरिकी डॉलर की आक्रामकता से कई बार भारतीय शेयर बाजार अचानक गिर जाता है और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। रही बात भारतीय रुपये के डॉलर का विकल्प बनने की, तो अभी यह आसान नहीं है। गौरतलब है कि किसी भी देश की मुद्रा को वैश्विक मुद्रा तेज रूप में पहचान हेतु उस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए और इसकी नीतियों में प्रगतिशीलता जरूरी है। भारत में ये दोनों बातें हैं और भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, परंतु अभी उसका एक लंबा सफर तय करना है। क्योंकि भारत का निर्यात बहुत कम है। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि भारत किसी अन्य मुद्रा को डॉलर के विकल्प के रूप में समर्थन देगा।



**चर्चा: स्कूल में हम क्या पढ़ाएं और
अपनी पाठ्य पुस्तकों को किस से बचाएं**

हिंसात्मक बृहुआ स हम आग आन वाली पीढ़ी को बचाना होगा। वृत्तांत के वे संर्दृ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य

हुआ, उस दौर में आनलाइन शक्ति की अपनी सीमाओं के कारण स्कूल पाठ्यक्रम को कम करने की ज़रूरत पड़ी, ताकि छात्रों पर से कोर्स का बोझ कम किया जा सके। इसके लिए संज्ञिका राजनातक हल्का में चल रहा है। राजनेता एवं कुछ कार्यकर्ता इस बहस को गति दें रहे हैं। इन बहसों में एक प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी

या अगर कहा किसी ऋषि का वर्णन है, तो उसकी भी जाति, कहीं कोई सामान्य चरित्र आ रहा है, वहां भी जाति, क्या यह प्रवृत्ति हमें एक समरस समाज बनाने में मदद वतमान से ज्यादा भाविष्य रचन का माध्यम एवं प्रणाली है। और अगर हमें जातिमुक्त जननांत्रिक समाज रचना है, तो उसमें टकरावें, तनावें हिंसात्मक बिंदुओं से हमें अपने आरं



पूर्सका का बचा सकता बहतर होगा। स्कूल के पाठ्यक्रमों में दुनिया के अनेक देशों में समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। इन संशोधनों एवं परिवर्तनों पर कभी-कभी विवाद भी होते हैं। पिछले दिनों हंगरी में स्कूल पाठ्यक्रमों में प्रवासी समूहों के पाठ्यगत प्रतिनिधित्व को लेकर लंबा विवाद चला। ब्रिटेन के स्कूल के पाठ्यक्रमों में विशेषकर ब्रिटेन राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ के इतिहास के साथ कैसे संगत बिठाई जाए एवं ब्रिटेन के स्कूल पाठ्यक्रमों में यूरोपीय संघ के इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस पर एक वैचारिक एवं विमर्शगत तनाव तो देखने को मिलता ही रहा है। वहीं जर्मनी में तो स्कूल के पाठ्यक्रमों में अपने राष्ट्रीय इतिहास को यूरोपीय संघ के इतिहास में

एनसीआरटी न अनक प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पांचवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 30-40 प्रतिशत और प्राइमरी कक्षाओं के लिए 10-15 प्रतिशत कोर्स को कम करने का निश्चय किया। इसमें शिक्षा पर बनी 331वीं संसद की स्थायी समिति के सुझावों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की दिशा-दृष्टि के आलोक में पाठ्यक्रम में से कुछ पाठों एवं वृतांतों को हटाया गया। इस संदर्भ में एनसीआरटी का मानना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। और ये निर्णय स्थितियों के अनुकूल लिए गए हैं। इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी डिजाइन नहीं है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। किंतु विवाद चलने ही हैं, तो चल रहे हैं। रोचक बात यह है कि

कर पाएगा? यह ठीक है कि गावा की गंवई कथाओं में चरित्रों की 'जाति' का आना-जाना सामान्य बात होती है। किंतु स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम जो एक सुसंगत एवं सुचित ढंग से एक बैहतर समाज रचने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उसमें उसी तरह के वृतांतों एवं चरित्रों के साथ उनकी 'जाति' के प्रत्यय का आना कितना ठीक है, हमें विचार करना होगा। अगर कोई कहता है कि 'जाति' तो हमारे समाज की सच्चाई है, अगर वह सच्चाई उसी रूप में हमारी पाठ्य पुस्तकों में आती है, तो इसमें गलत क्या है जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा सिर्फ जो है, उसी को नहीं दिखाती, जो हमें प्राप्त करना है, उसका माध्यम भी बनती है। वह 'जो यथार्थ है', उसे पाने ज्यादा 'जो आदर्श है', उन वालों पांडा का बचाना होगा। वृतांत के बैं संदर्भ जो समाज में अनेक तरह की गोलबंदी को जन्म देते हैं, अगर उनसे हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को बचा सकें, तो बहतर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी भारतीय में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों को छोटा, रचनात्मक एवं लचीला बनाने पर जोर देती है। वह हमें यह सुझार्ता है कि हम एक ऐसी शिक्षा की दुनिया बनाएं रखें, जिसमें हमारे बच्चों का कोमल सुकुमार मन रचनात्मक एवं सांस्कृतिक विकासमान हो सके। जाति, धर्म एवं अनेक तरह की कठियों से बचने और टकरावों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली जीवनी बनावाँ, हिंसात्मक गोलबंदियों को बचाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने से ज्यादा

